भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3400
दिनांक 08 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

एकीकृत बाल विकास सेवाओं का कार्यान्वयन

3400. डॉ. गुम्मा तनुजा रानीः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है;
(ख) यदि हाँ, तो पिछले वर्ष के दौरान आईसीडीएस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले बच्चों और महिलाओं की संख्या आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार कितनी है;
(ग) क्या आईसीडीएस के अंतर्गत सेवाओं की प्रदायगी से संबंधित देरी/कमी जैसी कोई समस्याएँ रही हैं; और
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा इन समस्याओं के समाधान और सेवा प्रदायगी में सुधार के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत, कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिए आंगनवाड़ी सेवाओं, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए योजना जैसे विभिन्न घटकों को व्यापक मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के अंतर्गत तीन प्रमुख खंडों में शामिल किया गया है जो निम्नलिखित हैं:

- 6 माह से 6 वर्ष की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं और आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14 से 18 वर्ष आयु की किशोरियों के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम के माध्यम से 'पोषण' हेतु न्यट्रीशन सपोर्ट;

- प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा [3-6 वर्ष] और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और प्रोत्साहन (0-3 वर्ष);

- आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगनवाड़ी सहित आंगनवाड़ी अवसंरचना;

मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत, वास्तविक सेवन और अनुशंसित आहार सेवन (आरडीआई) के बीच के अंतर को पाटने के लिए पूरे देश में स्थित आंगनवाड़ी केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से लाभार्थियों को वर्ष में 300 दिन पूरक पोषण प्रदान किया जाता है।

पोषण ट्रैकर के अंतर्गत, पोषण गुणवत्ता में सुधार और मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाओं में परीक्षण, प्रदायगी को सुदृढ़ बनाने और शासन में सुधार हेतु प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए पहल की गई हैं। प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के रूप में, 'पोषण ट्रैकर' एक सुदृढ़ आईसीटी सक्षम मंच है जो सेवाओं के तत्समय पर्यवेक्षण और प्रबंधन के संबंध में शासन में सुधार लाता है। इसके अतिरिक्त, अंतिम लाभार्थी तक सेवा प्रदायगी की ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए, घर ले जाने वाले राशन की प्रदायगी पर लाभार्थियों को एसएमएस अलर्ट आरंभ किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, घर ले जाने वाले राशन का लाभ उठाने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम (एफआरएस) को अनिवार्य कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत, शिकायत निवारण के लिए टोल-फ्री पोषण हेल्पलाइन (14408) भी आरंभ की गई है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पूरक पोषण वितरण में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही के लिए गुणवत्ता आश्वासन, कर्तव्यधारकों की भूमिका और उत्तरदायित्व, खरीद प्रक्रिया, आयुष अवधारणाओं के एकीकरण और पोषण ट्रैकर के माध्यम से डेटा प्रबंधन एवं निगरानी पर सुव्यवस्थित दिशानिर्देश जारी किए हैं। पूरक पोषण के अंतर्गत खाद्य पदार्थों की पोषण स्थिति और गुणवत्ता मानक, पारदर्शिता की निगरानी, राज्य, जिला और ग्राम स्तर पर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में की जा रही है।

'बच्चों में कुपोषण के प्रबंधन के लिए एक प्रोटोकॉल - सीएमएएम प्रोटोकॉल' आरंभ किया गया है, जिसमें आंगनवाड़ी स्तर पर कुपोषित बच्चों की पहचान और प्रबंधन के लिए विस्तृत पहल की गई हैं। इसमें रेफरल, पोषण प्रबंधन और पश्चात् देखरेख के लिए निर्णय लेना भी शामिल है।

मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत, की गई प्रमुख गतिविधियों में सामुदायिक जुटाव और जागरूकता अभियान चलाना शामिल हैं, जिसके माध्यम से लोगों को पोषण संबंधी पहलुओं के बारे में शिक्षित करने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित क्षेत्रीय भाषाओं में वीडियो, पैम्फलेट, फ़्लायर्स आदि के रूप में आईईसी सामग्री भी तैयार की गई है। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और अन्य हितधारकों के सहयोग से समुदाय आधारित कार्यक्रम, पोषण माह और पोषण पखवाड़ा आयोजित करके सामाजिक एवं व्यवहारिक बदलाव लाए गए हैं।

समुदाय आधारित कार्यक्रमों (सीबीई) ने पोषण पद्धतियों में बदलाव लाने में एक महत्वपूर्ण कार्यनीति के रूप में कार्य किया है। सीबीई, अन्य बातों के साथ-साथ, गर्भवती महिलाओं और दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों के जीवन में महत्वपूर्ण पड़ावों का उत्सव मनाने और आहार विविधता के साथ सही समय पर उचित पूरक आहार सुनिश्चित करने के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रसारित करने में मदद करते हैं। समुदाय आधारित कार्यक्रम जैसे अन्नप्राशन दिवस, सुपोषण दिवस (विशेष रूप से पतियों के उन्मुखीकरण पर केंद्रित) आयोजित किए जाते हैं, आंगनवाड़ी केंद्र में प्री-स्कूल के लिए तैयार होने की आयु प्राप्त कर लेने का उत्सव मनाया जाता है, पोषण में सुधार और बीमारी को कम करने, एनीमिया वॉश आदि के लिए जन स्वास्थ्य से संबंधित संदेश जारी किए जाते हैं तथा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं/चर्चाएं की जाती हैं।

जुलाई, 2024 तक पोषण ट्रैकर आंकड़ो के अनुसार मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत लाभान्वित होने वाले बच्चों और महिलाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।

****

अनुलग्नक

"एकीकृत बाल विकास सेवाओं का कार्यान्वयन" विषय पर दिनांक 08.08.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3400 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

जुलाई, 2024 तक पोषण ट्रैकर आंकड़ो के अनुसार महिलाओं और बच्चों का ब्यौरा:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बच्चे(0-6 वर्ष)	कुल महिलाएं (गर्भवती महिलाएं+ स्तनपान कराने वाली माताएं)
1	असम	2846298	209440
2	उत्तर प्रदेश	19566561	2701815
3	राजस्थान	3756261	612453
4	दिल्ली	564242	118851
5	छत्तीसगढ़	2252756	299357
6	आंध्र प्रदेश	2679400	471231
7	उत्तराखंड	656401	117616
8	गोवा	49819	7767
9	पंजाब	1418609	182196
10	मिजोरम	107944	9770
11	संघ राज्य क्षेत्र-चंडीगढ़	37919	6608
12	बिहार	9699352	1030341
13	झारखंड	2886628	285892
14	ओडिशा	3467165	494586
15	पुद्दुचेरी	29525	6432
16	तेलंगाना	1798120	194446
17	त्रिपुरा	301889	28262
18	मेघालय	370956	14751
19	हरियाणा	1754547	231207
20	पश्चिम बंगाल	7753936	975180
21	अरुणाचल प्रदेश	80987	4441
22	नागालैंड	107685	3278

23	हिमाचल प्रदेश	491275	71059
24	तमिलनाडु	3555264	511769
25	मध्य प्रदेश	6668072	835061
26	जम्मू और कश्मीर	733200	83358
27	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	10873	1422
28	लक्षद्वीप	3655	794
29	गुजरात	3118233	413929
30	महाराष्ट्र	6181015	626546
31	मणिपुर	264793	18588
32	लद्दाख	16667	1594
33	कर्नाटक	3691084	486109
34	केरल	1932489	222304
35	सिक्किम	30773	2847
36	दादरा और नगर हवेली - दमन और दीव	33748	5899
कुल		**8,89,18,141**	**1,12,87,199**

****